Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अगस्त (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- ➢ टिहरी की श्रुतिका राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिये चयनित 3
- ➢ 19वें एशियाई गेम्स के लिये बागेश्वर के रोहित दानू भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल 4
- ➢ चीन सीमा पर बनेंगी तीन सुरंग 4
- ➢ हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी चौरासी कुटिया 5
- ➢ 200 साल में पहली बार मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा 6
- ➢ काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज़ पर बनेगा हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर 7
- ➢ उत्तराखंड की पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार 7
- ➢ हृदय रोग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रति माह छह लाख रुपए मानदेय, केंद्र सरकार ने दी मंज़ूरी 8
- ➢ यूसर्क के पाँच विज्ञान चेतना केंद्रों को गोद लेगा श्रीदेव सुमन विवि 9
- ➢ तीलू रौतेली राज्यस्तरीय पुरस्कार 2022-23 में 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मिला अवॉर्ड 9
- ➢ प्रदेश में अब वेलनेस, योग और पंचकर्म सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य 10
- ➢ उत्तराखंड की जेलों में बंद 39 कैदियों को मिलेगी 'आजादी' 11
- ➢ शासन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (एमएसएमई) की अधिसूचना जारी की 12
- ➢ श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में दोबारा पीजी पर रोक, नियम लागू करने वाला राज्य व देश का पहला विवि 13
- ➢ मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की 13 बड़ी घोषणाएँ 14
- ➢ प्रदेश में 'मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक' से नवाज़े गए पुलिसकर्मी 16
- ➢ उत्तराखंड के एसआई भगवान सिंह को मिला केंद्रीय गृहमंत्री पदक 16
- ➢ राज्यपाल ने किया क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ 17
- ➢ Global Investors Summit: समिट से प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य 19
- ➢ रोपवे से जुड़ेगा कार्तिक स्वामी मंदिर 20
- ➢ जल्द उठेगा जागेश्वर और बद्रीनाथ के शिलालेखों के रहस्य से पर्दा 21
- ➢ मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22
- ➢ यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, जल्द होगा लागू 22
- ➢ स्मार्ट स्नेक-ट्रैपिंग डिवाइस 23
- ➢ पीआरडी जवानों की डयूटी के दौरान मौत पर आश्रितों को मिलेंगे दो लाख रुपए 24
- ➢ राष्ट्रीय फलक पर छाई उत्तराखंड की बेटी सृष्टि, फिल्म 'एक था गाँव' को मिला अवॉर्ड 25
- ➢ चमोली ज़िले को मिला राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवॉर्ड 26
- ➢ उत्तराखंड में इसी साल से एमबीबीएस छात्रों को मिलेगा हिन्दी में पढ़ने का विकल्प 27
- ➢ उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल छात्रों के लिये कीं कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ 28
- ➢ उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त 29
- ➢ मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 29
- ➢ चंपावत में बनेगा राज्य का तीसरा साइंस सेंटर 30

नोट :

उत्तराखंड

टिहरी की श्रुतिका राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

31 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार टिहरी की श्रुतिका सिलस्वाल का चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिये हुआ है। उनका चयन राष्ट्रमंडल देशों के कुल 50 युवाओं में किया गया है, जिसमें चार भारतीय शामिल हैं। सितंबर में उन्हें लंदन में यह पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले युवाओं को दिए जाते हैं।
- राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिये सूची में चार भारतीयों सहित कुल 50 लोगों के नाम हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वाले ये लोग सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को हासिल करने में योगदान देने संबंधी पहलों में शामिल हैं।
- भारत के अक्षय मकर को SDG 13 जलवायु परिवर्तन, सौम्या डाबरीवाल को SDG 5 लैंगिक समानता, कौशल शेट्टी को SDG 11 टिकाऊ शहर तथा समुदाय और श्रुतिका सिलस्वाल को SDG 4 गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये चयनित किया गया है।
- विदित है कि श्रुतिका सिलस्वाल सिंपल फाउंडेशन के साथ टिहरी गढ़वाल में शिक्षा के सुधार पर काम कर रही हैं। वह फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर हैं। यह संगठन सरकारी स्कूलों के बच्चों की सहायता करता है।
- फिलहाल वह पाँच स्कूलों में अपना प्रोजेक्ट चला रही हैं। उनका सपना देशभर के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार पर है। इसके लिये उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो बच्चों को भावनात्मक रूप से काफी मज़बूत बनाते हैं।
- मूल रूप से टिहरी के कखीलभेलधार की रहने वाली श्रुतिका को इससे पहले 'टीचर फॉर इंडिया' और 'दलाईलामा फेलोशिप' भी मिल चुका है।
- श्रुतिका के पिता विनोद सिलस्वाल एमआईटी कॉलेज ढालवाला में, जबकि मां मीनाक्षी चंबा के जीआईसी नागणी में शिक्षिका हैं।
- श्रुतिका कोविड के बाद शिक्षा के लिये पहाड़ से होने वाले पलायन से आहत हैं और वह नहीं चाहती कि कोई प्राथमिक शिक्षा के लिये अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाए।

The Vision

नोट :

- राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिये चयनित 50 युवाओं में से 20 को विजेता चुना जाएगा। ये युवा 14 सितंबर को लंदन में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र आदि प्रदान किया जाएगा।
- आमतौर पर 20 नाम चुने जाते थे, जिनमें से पाँच क्षेत्रीय विजेता चुने जाते थे, लेकिन इस वर्ष राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 50 युवाओं के नाम शामिल किये गए हैं।

19वें एशियाई गेम्स के लिये बागेश्वर के रोहित दानू भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2023 को 19वें एशियाई गेम्स के लिये भारतीय फुटबॉल टीम की घोषणा हुई, जिसमें उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर रोहित दानू भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- शानदार फारवर्डर रोहित का चयन 23 सितंबर से 8 अक्तूबर तक चीन के हांग्जो में होने वाले एशियाई गेम्स के लिये भारतीय टीम में हुआ है। रोहित दानू सुनील छेत्री की कप्तानी वाली देश की फुटबॉल टीम से खेलते नज़र आएंगे।
- बागेश्वर के बघर गाँव निवासी रोहित दानू ने काफी छोटी उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने फुटबॉल की बारीकियाँ बागेश्वर के कोच नीरज पांडेय से सीखीं।
- वह प्रदेश की अंडर-14 टीम का हिस्सा रहे। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बूते वर्ष 2017 में 15 वर्ष की उम्र में भारतीय अंडर-17 टीम का हिस्सा बन गए। रोहित ने वर्ष 2017 में फीफा विश्व कप अंडर 17 में देश का प्रतिनिधित्व किया। रोहित भारतीय अंडर-19, अंडर-23 का हिस्सा भी रहे।
- रोहित दानू का हाल ही में बंगलूरू एफसी के साथ तीन साल का करार हुआ है। वह 2020 में इंडियन सुपर लीग क्लब हैदराबाद के साथ तीन साल के लिये जुड़े थे।

चीन सीमा पर बनेंगी तीन सुरंग

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडेय ने बताया कि भारत-चीन सीमा पर दो अलग-अलग घाटियों में स्थित आईटीबीपी की दो चौकियों को आपस में जोड़ने और सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दोनों घाटियों को सुरंग मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- इससे पिथौरागढ़ के जौलिंगकांग और चमोली के लप्थल के बीच की दूरी 490 किमी. से घटकर 42 किमी. रह जाएगी। इसके लिये करीब 57 किमी. की तीन सुरंगें और 20 किमी. सड़क मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है। सामरिक महत्त्व की इस परियोजना पर अब केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है।
- भारत-चीन सीमा में वर्तमान में कोई ऐसा सीधा मार्ग नहीं है, जो पिथौरागढ़ के जौलिंगकांग आईटीबीपी पोस्ट को चमोली के लप्थल में आईटीबीपी पोस्ट से सीधे जोड़ता हो। सामरिक रूप से अति महत्त्वपूर्ण इन दोनों पोस्टों को 57 किमी. की तीन सुरंगों का निर्माण कर 490 किमी. की दूरी को कम किया जा सकता है।
- यह सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, सेना, एसएसबी एवं आईटीबीपी और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
- राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे अपने प्रस्ताव में राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को बनाए रखने के साथ पलायन रोकने के लिये इस परियोजना को महत्त्वपूर्ण बताया है।
- पाँच किमी. की होगी पहली सुरंग:
  - पिथौरागढ़ ज़िले के जौलिंगकांग (व्यास घाटी) से बेदाग (दारमा घाटी) तक की यात्रा शिमला पास होते हुए पूरी की जाती है, जो लगभग

नोट :

पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। इस स्थान पर सड़क मार्ग का निर्माण करना बहुत कठित है।

- जौलिंगकांग के मध्य पाँच किमी. सुरंग का निर्माण वेदांग से गो एवं सिपु तक 20 किमी. सड़क मार्ग सहित किये जाने से बीआरओ एवं सीपीडब्ल्यूडी की ओर से निर्मित तवाघाट से बेदांग तक के मार्ग को जोड़ा जाएगा। यह जौलिंगकांग एवं बेदांग की दूरी 161 किमी. कम कर देगा।

- 22 किमी. लंबी होगी दूसरी सुरंग: वर्षभर बर्फ से ढके रहने वाले पैदल मार्ग सिपू से तोला तक मोटर मार्ग का निर्माण भी कठिन है। सिपु से तोला के मध्य लगभग 22 किमी. लंबाई की सुरंग का निर्माण किये जाने से दारमा वैली और जोहार वैली एक-दूसरे से जुड़ जाएंगी।
- 30 किमी लंबी होगी तीसरी सुरंग: पिथौरागढ़ के मिलम से चमोली के लप्थल तक का पैदल मार्ग भी वर्षभर बर्फ से ढका रहता है। इस भाग में भी सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना मुश्किल है। मिलम से लप्थल तक 30 किमी. टनल का निर्माण होने से पिथौरागढ़ की जोहार घाटी एवं चमोली का लप्थल सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा।

हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी चौरासी कुटिया

चर्चा में क्यों?

3 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम स्थित ऐतिहासिक स्थल चौरासी कुटिया को हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिये एचसीपी डिज़ाइन मैनेजमेंट कंपनी मास्टर प्लान तैयार करेगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि तीर्थनगरी में महर्षि महेश योगी की तपस्थली चौरासी कुटिया दुनिया के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बैंड ग्रुप बीटल्स की याद से जुड़ी है। देश-दुनिया के पर्यटक चौरासी कुटिया आते हैं, लेकिन अभी यह स्थल पर्यटन के लिहाज से विकसित नहीं हो पाया है।
- अब सरकार ने इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। चौरासी कुटिया राजाजी टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में होने से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी अनुमति ली जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1961 में महर्षि महेश योगी ने राजाजी टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि में चौरासी कुटिया आश्रम का निर्माण किया था। उन्होंने करीब 40 वर्षों के लिये वन भूमि को लीज़ पर लिया था। इस दौरान उन्होंने आश्रम में 140 गुंबदनुमा कुटिया और 84 छोटी-छोटी ध्यान योग की कुटिया व अन्य निर्माण किया था।
- वर्ष 1968 में इंग्लैंड के मशहूर बीटल्स ग्रुप के चार सदस्य जॉन लेनन, पॉल मकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार चौरासी कुटिया में ध्यान-योग करने के लिये आए थे। ये लोग कुटिया नंबर नौ में ध्यान करते थे।

- वे यहाँ करीब चार महीने रुके थे। इन चार महीनों में उन्होंने यहाँ 40 गानों की धुन तैयार की थी, जिन्हें विदेशी आज भी मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वन भूमि की लीज समाप्त होने के चलते महर्षि महेश योगी इस कुटिया को वर्ष 1989 में छोड़कर हॉलैंड चले गए। वर्ष 2000 में वन विभाग ने इस आश्रम का अधिग्रहण कर लिया।

200 साल में पहली बार मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तहसील बनने के बाद शहर के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और शहर की प्रशासनिक व्यवस्था मज़बूत होगी।

प्रमुख बिंदु

- इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी ने बताया कि मसूरी की स्थापना के दो सौ साल में कभी पूर्ण तहसील नहीं रही। ब्रिटिश काल में मेरठ से कमिश्नरी संचालित होती थी। 1840 से शहर मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई थी।
- उस समय जो सुविधाएँ इंग्लैंड में होती थीं, वह सभी सुविधाएँ अंग्रेज़ों ने मसूरी में उपलब्ध कराईं। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिये अंग्रेज़ों ने 1850 में मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। अब मसूरी को सरकार ने तहसील का दर्जा दिया है।
- पहाड़ी स्टेशनों की रानी मसूरी इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिये प्रसिद्ध है। देहरादून से 38 किलोमीटर दूर मसूरी अपनी हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों एवं जीवों के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है।

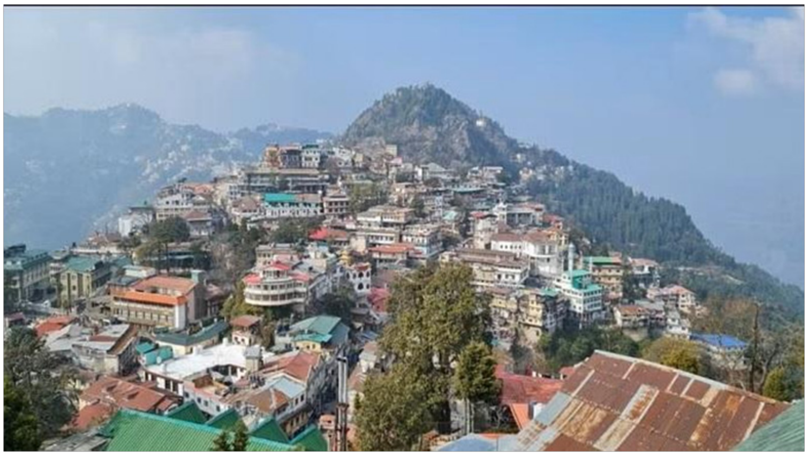

काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज़ पर बनेगा हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर

चर्चा में क्यों?

3 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज़ पर हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही प्लान बनाने वाली कंपनी को ही गंगा कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनाने के लिये चयनित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश शहर का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिये हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना तैयार की जाएगी।
- हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला (दूधाधारी चौक), हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र (दक्ष मंदिर एवं संन्यास रोड), भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम (भारत माता मंदिर क्षेत्र) के क्षेत्र और ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास कोर क्षेत्र, आईएसबीटी के पास का क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि के क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है।
- गंगा कॉरिडोर का काम ढाई साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये सरकार हरिद्वार, ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी लिमिटेड का गठन करेगी। परियोजना की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति और परियोजना के अनुश्रवण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया जाएगा।

उत्तराखंड की पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार

चर्चा में क्यों?

6 अगस्त, 2023 को कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में सेब उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिये पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति में पाँच हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में नए सेब के बगीचे लगाने के लिये सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी। 0.2 से 20 हेक्टेयर भूमि पर किसान सेब बगीचे तैयार कर सकते हैं।

नोट :

- कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस नीति पर प्रदेश के किसानों से भी सुझाव लिये जाएंगे। जिन्हें नीति में शामिल किया जाएगा। इसके बाद ही नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
- विदित है कि प्रदेश में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर ज़िले को छोड़ शेष 11 ज़िलों के पर्वतीय क्षेत्रों में सेब का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से सेब उत्पादन में पीछे हैं।
- प्रदेश में उत्तरकाशी सेब उत्पादन में अग्रणी है। कुल 25785 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 62 हज़ार मीट्रिक टन सेब का उत्पादन किया जाता है।
- पहली बार सेब नीति लागू कर राज्य सरकार का उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर है। जिन किसानों के पास कम ज़मीन है, उन्हें भी सेब की खेती के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- नीति में 0.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक सेब बगीचे लगाने के लिये सरकार उन्नत किस्म के सेब के पौधे मुहैया कराएगी। इसके अलावा सेब के पौधे मुहैया कराने, तकनीकी जानकारी के लिये कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

हृदय रोग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रति माह छह लाख रुपए मानदेय, केंद्र सरकार ने दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

7 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में हृदय रोग विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कॉर्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उच्च पैकेज (प्रति माह छह लाख रुपए मानदेय) देने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- पर्वतीय ज़िलों में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिये प्रदेश सरकार ने 'यू कोट वी पे' फार्मूले को लागू किया है। इसके तहत विभिन्न रोग के स्पेशलिस्ट को अधिकतम चार लाख रुपए तक प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है।
- यू कोट वी पे फार्मूले के तहत स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संविदा पर भर्ती की जा रही है। तीसरे चरण के लिये आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 22 अगस्त को साक्षात्कार होंगे। फार्मूले के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात होने वाले डॉक्टरों को उच्च मानदेय दिया जाएगा।

नोट :

- स्वास्थ्य सचिव डॉ आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब स्थापित की गई है, जहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों को तैनाती दी जाएगी।

यूसर्क के पाँच विज्ञान चेतना केंद्रों को गोद लेगा श्रीदेव सुमन विवि

चर्चा में क्यों ?

6 अगस्त, 2023 को प्रदेश में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार व छात्रों में वैज्ञानिक रुचि के विकास के लिये उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (यूसर्क) और टिहरी गढ़वाल के बादशाही थौल स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के बीच एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यूसर्क की निदेशक प्रो. अनीता रावत व विवि के कुलपति प्रो. एनके जोशी ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं ।
- इस समझौते के आधार पर दोनों संस्थान प्रदेश में विज्ञान शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों को स्तरीय बनाने का काम करेंगे।
- श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय यूसर्क की ओर से संचालित 200 से अधिक विज्ञान चेतना केंद्रों में से कम-से-कम पाँच केंद्रों को गोद लेकर उनमें विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का संचालन करेगा। विद्यालय के छात्रों को अपने विश्वविद्यालय से विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करेगा।
- श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जोशी ने कहा कि इस समझौते से जहाँ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों को यूसर्क की वैज्ञानिक गतिविधियों का भरपूर लाभ मिलेगा, वहीं अन्य छात्र भी दोनों संस्थाओं के इस प्रयास से लाभान्वित होंगे।

तीलू रौतेली राज्यस्तरीय पुरस्कार 2022-23 में 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मिला अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को तीलू रौतेली राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वीरांगनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार इनके सम्मान और सशक्तीकरण के लिये संकल्पबद्ध है।
- इन्हें मिला सम्मान :
  - पिथौरागढ़ की निवेदिता कार्की मुक्केबाज़ी के अपने सपने को पूरा करने के लिये अपनी बोर्ड परीक्षा छोड़कर स्वीडन में स्वर्ण पदक जीतने वाली और चीन में 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य जीतने वाली चमोली की मानसी नेगी सहित 14 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्यस्तरीय पुरस्कार मिला।
  - खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट अल्मोड़ा की गरिमा जोशी, राज्यस्तरीय पैरा खिलाड़ी बागेश्वर की मोहिनी कोरंगा, कला एवं योग के क्षेत्र में चंपावत की शांभवी मुरारी, पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में देहरादून की अमीशा चौहान, खेल में ताइक्वांडो की राज्यस्तरीय खिलाड़ी हरिद्वार की दिव्या भारद्वाज को यह पुरस्कार मिला है।
  - इनके अलावा साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में नैनीताल की मंजू पांडे, महिला रोज़गार के क्षेत्र में पौड़ी की नूतन पंत, पर्यावरण में रुद्रप्रयाग की प्रीति, खेल में टिहरी की हिमानी, खेल दिव्यांग वर्ग में उधमसिंह नगर की नीलिमा राय एवं साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्तरकाशी की ममता व नैनीताल की कमला अरोड़ा को तीलू रौतेली पुरस्कार मिला।
- राज्य सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम से दिये जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 20 हज़ार रुपए बढ़ा दी है। अब इसे 31 हज़ार से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपए कर दिया गया है।
- वहीं, राज्यस्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पुरस्कार की राशि में 30 हज़ार रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब इसे 21 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपए कर दिया गया है।
- सभी वीरांगनाओं और कार्यकर्त्ताओं को सम्मान की राशि ऑनलाइन उनके खाते में जमा कराई गई है।

प्रदेश में अब वेलनेस, योग और पंचकर्म सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के आयुष सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश में संचालित वेलनेस, योग और पंचकर्म सेंटरों के लिये अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिये पहली बार आयुष विभाग ने नियमावली तैयार की है, जिसमें सेंटरों के संचालन के लिये मानक तय किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसमें पहले एक साल के लिये पंजीकरण नि:शुल्क होगा। इसके बाद पंजीकरण नवीनीकरण के लिये 200 रुपए का शुल्क लिया जाएगा।
- विदित है कि प्रदेश के ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत अन्य ज़िलों में निजी आयुष वेलनेस, योग और पंचकर्म केंद्र चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन सेंटरों का आयुर्वेद विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही सेंटर बिना मानकों के चल रहे हैं।
- इसे देखते हुए पहली बार वेलनेस, योग और पंचकर्म केंद्रों के लिये नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया। शासन ने प्रस्ताव मंज़ूरी के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा है। जल्द ही मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही नियमावली को लागू किया जाएगा।
- नियमावली में वेलनेस, योग और पंचकर्म सेंटरों की सुविधाओं के आधार पर रेटिंग की जाएगी।
- इसमें बेहतर सुविधाएँ देने और मानकों पर खरा उतरने वाले सेंटरों को फाइव स्टार रेटिंग मिलेगी। इसके बाद फोर व थ्री स्टार रेटिंग होगी। आयुष नीति में गुणवत्तायुक्त सेवाएँ देने वाले थ्री स्टार से ऊपर की रेटिंग वाले सेंटरों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा।
- आयुर्वेद विभाग के माध्यम से वर्तमान में 300 से अधिक वेलनेस, योग और पंचकर्म सेंटर संचालित किये जा रहे हैं, लेकिन योग और वेलनेस चिकित्सा के नाम पर चल रहे निजी सेंटरों का रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है।
- विभाग का अनुमान है कि ऋषिकेश शहर में ही 100 से अधिक निजी योग केंद्र चल रहे हैं।
- उत्तराखंड को आयुष वेलनेस का हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वेलनेस और योग के लिये राज्य में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिले।

उत्तराखंड की जेलों में बंद 39 कैदियों को मिलेगी 'आजादी'

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के डीआईजी जेल धदिराम मौर्य ने प्रदेश की सभी जेलों को जेलों में बंद 39 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगाँठ पर रिहा करने के आदेश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि इस संबंध में गत चार अगस्त को शासन ने आदेश जारी किया था।
- आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों पर देशभर की जेलों से कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के अच्छे व्यवहार वाले कैदियों की सज़ा माफी के संबंध में विचार-विमर्श किया था।

- इन कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।
- ये सब कैदी विभिन्न अपराधों में दोषसिद्ध किये गए हैं। इनके अलावा प्रदेश में छह विदेशी मूल के कैदियों को भी रिहा करने पर विचार चल रहा है। ये सब कैदी विभिन्न जेलों में बंद हैं।

शासन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (एमएसएमई) की अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) की स्वीकृति के बाद शासन ने राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (एमएसएमई) की अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति में राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में नए उद्योगों में निवेश और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये सब्सिडी में बढ़ोतरी की है।
- नीति के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगों को नए उद्योगों में निवेश करने पर सरकार पाँच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
- इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिये मंडी शुल्क में पाँच साल तक 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- पहाड़ों में निवेश करने पर 50 लाख से चार करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम सब्सिडी 1.50 करोड़ होगी।
- नीति में महिलाओं, एससीएसटी, दिव्यांगों के स्वामित्व वाले उद्योगों को पाँच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इन्हें सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग के लिये पाँच लाख, लघु श्रेणी के लिये 10 लाख और मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिये 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
- नीति में चिह्नित ए और बी श्रेणी के क्षेत्रों में कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को पाँच साल तक मंडी शुल्क में प्रति वर्ष 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

- इसके अलावा उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ट्रेड मार्क, क्वालिटी मार्किंग, पेटेंट कराने के लिये अधिकतम एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- उद्योगों को दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन के लिये राज्य व ज़िला स्तर पर प्राधिकृत कमेटी गठित की जाएगी। इसमें राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष उद्योग महानिदेशक होंगे। ज़िला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष संबंधित ज़िलाधिकारी होंगे।
- इसके अलावा शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उद्योग सचिव होंगे।

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में दोबारा पीजी पर रोक, नियम लागू करने वाला राज्य व देश का पहला विवि

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल (बादशाहीथौल) स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने इस साल से उन छात्रों के दोबारा पीजी दाखिले पर रोक लगा दी है, जो पूर्व में विश्वविद्यालय से पीजी कोर्स कर चुके हैं। यह नियम लागू करने वाला यह विश्वविद्यालय राज्य व देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया।

प्रमुख बिंदु

- विश्वविद्यालय के कुलसचिव के.आर भटे ने बताया कि कई छात्र एक बार पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रसंघ चुनाव के लिये दोबारा पीजी में दाखिला ले लेते हैं। ऐसे छात्रों को रोकने के लिये ही ये निर्णय लिया गया है। हालाँकि, इसकी पहचान कैसे होगी, वह यह स्पष्ट नहीं कर पाए।
- हाल ही में श्रीदेव सुमन विवि ने एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिये प्रवेश नियम 2023 जारी किये हैं।
- इसकी बिंदु संख्या 1.15 (क) के मुताबिक, श्रीदेव सुमन विवि के नामांकित छात्र के रूप में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होने के बाद एक विषय से पीजी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को किसी भी दशा में अन्य विषय में एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम. में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
- विदित है कि नई शिक्षा नीति में जहाँ सरकार द्वारा सभी छात्रों को मुख्य विषयों के साथ ही पसंद के विषय चुनने, पढ़ाई के दौरान गैप होने पर दोबारा एकेडमिक क्रेडिट बैंक की मदद से कोर्स करने की आज़ादी दी गई है तो श्रीदेव सुमन विवि ने इसके उलट एक बार पीजी करने पर दूसरे पीजी पर रोक लगा दी है।

- मसलन, अगर कोई छात्र एमए हिन्दी में करता है और वह कोर्स पूरा करने के बाद एम.ए. हिस्ट्री या एम.ए. पॉलिटिकल साइंस में करना चाहता है तो उसे श्रीदेव सुमन विवि में दाखिला नहीं मिलेगा। इसके लिये उसे किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाना होगा।
- गौरतलब है कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित राज्य व देश के किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा नियम लागू नहीं है, जो कि एक छात्र को एक विश्वविद्यालय से दोबारा दूसरे विषय से पीजी करने से रोकता हो।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की 13 बड़ी घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिये 13 बड़ी घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाएँ:

- आमजन को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुँचाने के लिये एक 'खनिज प्रसंस्करण पोर्टल' बनाया जाएगा। इससे एक ओर खनिजों की कालाबाज़ारी रुकेगी तो वहीं लोगों को सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
- दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिये 'मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना' प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिये तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये उनके विषयों की पुस्तक हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिये जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।

- राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा।
- राज्य में एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोज़गार सृजन के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना' प्रारंभ की जाएगी।
- पर्वतीय क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- मज़दूर वर्ग के बच्चों के लिये उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिये मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- विकासनगर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसके ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिये एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
- प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्द्धन के लिये जल्द ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
- सीमांत गाँव के जनजातीय इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
- एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी व प्रभावी रहेगी।
- प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये तथा इनके उत्पादों की बिक्री के लिये यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी।

प्रदेश में 'मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक' से नवाज़े गए पुलिसकर्मी

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुलिस के चार पुलिस अधिकारियों को 'मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक' से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इनके अलावा मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी को सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न और एक को विशिष्ट कार्य के लिये सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न दिया तथा पुलिस अधिकारियों को मेडल लगाकर सम्मानित किया।
- विशिष्ट कार्य के लिये मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक:
  - भदाणे विशाखा अशोक, एसपी रुद्रप्रयाग
  - रेखा यादव, एसपी क्राइम, हरिद्वार
  - अमित श्रीवास्तव, द्वितीय परिसहाय राज्यपाल
  - सरिता डोबाल, एसपी सिटी देहरादून
- सराहनीय सेवा के लिये सेवा के आधार पर सेवा सम्मान चिह्नः
  - हरीश वर्मा, डिप्टी कमांडेंट, 46वीं बटालियन पीएसी
- विशिष्ट कार्य के लिये सराहनीय सेवा सम्मान चिह्नः
  - रेनू लोहानी, एएसपी, विजिलेंस

उत्तराखंड के एसआई भगवान सिंह को मिला केंद्रीय गृहमंत्री पदक

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर को ऑनर किलिंग करने वालों को मृत्युदंड दिलाने के लिये केंद्रीय गृहमंत्री पदक से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उन्हें यह पदक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में दिया गया।
- विदित है कि 18 मई, 2018 को हरिद्वार के खानपुर में स्वजनों के विरुद्ध जाकर शादी करने पर दो सगे भाईयों कुलदीप व अरुण और ममेरे भाई राहुल ने अपनी बहन प्रीति की कुल्हाड़ी व फावड़े से काटकर नृशंस हत्या कर दी थी।
- इस संबंध में मृतका के पति बृजमोहन की तहरीर पर थाना खानपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन समय में थानाध्यक्ष खानपुर के पद पर तैनात उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर द्वारा की गई थी।
- उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर द्वारा त्वरित गति से विवेचना करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध 13 अगस्त, 2018 को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया।
- उनके द्वारा एकत्र किये गए साक्ष्यों, समय पर प्रस्तुत किये गवाहों, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं ठोस पैरवी के अधार पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्सर, हरिद्वार द्वारा अभियुक्त कुलदीप, अरुण व राहुल को धारा 302 भादवि के रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी के अपराध के लिये मृत्युदंड एवं अर्थदंड से दंडित किया गया था।

राज्यपाल ने किया क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग के कंटिन्युड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट (क्लैप) का शुभारंभ किया, जिसके तहत बच्चे ई-लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही राज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई-लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया।
- शिक्षा विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से क्लैप तैयार किया गया है। इस सचल ई-लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप हैं, जिनमें शिक्षण सामग्री संरक्षित है।
- यह वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक से कक्षा-12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में 'डिजिटल सामग्री' उपलब्ध कराएगा।
- वाहन में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित लर्निंग चैनल, दिशा और ई-पाठशाला उपलब्ध हैं। छात्र इसमें अधिगम के साथ-साथ स्वमूल्यांकन भी कर सकेंगे।

नोट :

- यह वाहन वर्तमान में जनपद टिहरी के विद्यालयों में रूट चार्ट के आधार पर संचालित किया जाएगा।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एनसीईआरटी के विशेष प्रयासों से ई-कंटेट युक्त डिजिटल वाहन बच्चों को नवीन शिक्षण विधाओं और पाठ्यचर्चा से परिचित कराने में उपयोगी साबित होगा।
- यह वाहन तकनीकी के माध्यम से ज्ञान की ज्योति दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों तक पहुँचाएगा। ई-एजुकेशन वाहन प्रदेश के दूरस्थ विद्यालयों में भ्रमण कर अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करेगा।
- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष प्रदेश की रैंकिंग 35वें पायदान पर थी, जो इस वर्ष 17वें पायदान पर पहुँच गई है। राज्य सरकार का प्रयास प्रदेश को टॉप 10 रैंकिंग में लाने का है।

नोट :

Global Investors Summit: समिट से प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समिट के लिये प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये समिट से पहले लगभग 25 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोज़गार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने वाले के लिये कई विभागों से अनुमति की फाइल रुकेगी नहीं। निवेशकों को सभी अनुमतियाँ देने के लिये समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।
- बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने, राज्य की आर्थिकी में वृद्धि के लिये कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिये और क्या बेहतर प्रयास किये जा सकते हैं, इसके लिये औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिये गए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिये शांति व्यवस्था के साथ ही बेहतर मानव संसाधन भी उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि उन्हें जिन-जिन क्षेत्रों में दक्ष मानव संसाधन की ज़रूरत है, वह बताई जाए। सरकार की ओर से ऐसे क्षेत्रों में युवाओं को देने प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्थाएँ की जाएगी।
- सीएम ने कहा कि शीघ्र ही अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम शुरू होने वाला है। इस कॉरिडोर के बनने से उद्योगों को सुविधा मिलेगी।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिये स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में इंटीग्रेटेड कंटेनर डिपो स्थापित किया गया है। सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति लागू की है। इससे आधारभूत ढाँचे के विकास में मदद मिलेगी।
- इन्वेस्टर्स समिट को लेकर निवेशकों ने कई सुझाव दिये, जिसमें निवेश के लिये लैंडबैंक बनाने, जड़ी-बूटी की खेती को बढ़ावा देने, राज्य में संचालित उद्योगों का सर्वे करने, उत्तराखंड में रिसर्च सेंटर बनाने, चिंतन व अध्यात्म के रूप में राज्य में निवेश की योजना पर काम करने का सुझाव दिया।

रोपवे से जुड़ेगा कार्तिक स्वामी मंदिर

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि कार्तिक स्वामी मंदिर तक सरल व सुलभ पहुँच के लिये रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिये प्री-फिजिबिलिटी सर्वे हो चुका है। कार्तिक स्वामी के पैदल मार्ग में भी सुविधाएँ जुटाई जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के क्रौंच पर्वत पर स्थित है, जिसे कार्तिक स्वामी कहा जाता है। इस मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुँच को आसान बनाने के लिये इसे रोपवे से जोड़ा जाएगा।
- मंदिर के बेस पॉइंट कनकचौरी से कार्तिक स्वामी तक 1.4 किमी लंबा रोपवे बनेगा, जिसके लिये प्री-फिजिबिलिटी सर्वेक्षण भी हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार आगामी सितंबर तक रोपवे निर्माण की अंतिम डीपीआर भी बन जाएगी।

- जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के 360 से अधिक गाँवों के आराध्य के रूप में पूजनीय भगवान कार्तिकेय के दर्शनों के लिये वर्षभर श्रद्धालु कार्तिक स्वामी मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर पहुँचने के लिये श्रद्धालुओं को कनचौरी से लगभग चार किमी. की चढ़ाई तय करनी होती है, लेकिन अब मंदिर को रोपवे से जोड़ने की कार्ययोजना बन चुकी है।
- कनकचौरी से मंदिर तक बनने वाले रोपवे की लंबाई 1.4 किमी होगी। रोपवे बनने से कनकचौरी से 10 मिनट में ही कार्तिक स्वामी मंदिर पहुँचा जा सकेगा।
- कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघन सिंह नेगी ने बताया कि मंदिर तक सुविधाएँ उपलब्ध होने से तीर्थाटन के साथ रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
- भगवान कार्तिकेय के मंदिर कार्तिक स्वामी की यात्रा को सरल-सुलभ बनाने के लिये चंद्रापुरी-बाजबड्डू-कार्तिक स्वामी 10 किमी. सड़क भी स्वीकृत हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ डिवीज़न द्वारा जल्द ही मार्ग का सर्वेक्षण किया जाएगा।

जल्द उठेगा जागेश्वर और बद्रीनाथ के शिलालेखों के रहस्य से पर्दा

चर्चा में क्यों?

20 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के सहायक अधीक्षण पुरातत्त्वविद् केबी शर्मा ने बताया कि अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और चमोली स्थित बद्रीनाथ के प्राचीन शिलालेखों के रहस्य से जल्द पर्दा उठेगा। इसके लिये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने एपिग्राफी शाखा लखनऊ को पत्र भेज दिया है।

प्रमुख बिंदु

- जागेश्वर धाम स्थित महामृत्युंजय समेत कुछ अन्य मंदिरों की दीवारों में प्राचीन लिपि उत्कीर्ण है। महामृत्युंजय मंदिर के दो विशालकाय शिलालेख अब पुरातात्त्विक संग्रहालय में संरक्षित हैं। इन शिलालेखों में उत्कीर्ण लिपि का अब तक अनुवाद नही हो सका है। बद्रीनाथ धाम में भी शिलालेख में उत्कीर्ण प्राचीन लिपि लोगों के लिये रहस्य बनी हुई है।
- इसी को देखते हुए बीते दिनों एएसआई के अधिकारी केबी शर्मा ने एपिग्राफी शाखा को पत्र भेजकर जागेश्वर और बद्रीनाथ धाम स्थित प्राचीन शिलालेखों में उत्कीर्ण लिपि का अनुवाद करने के लिये विशेषज्ञों की टीम भेजने का आग्रह किया है।
- रिसर्च प्रक्रिया पूरी होने के बाद एएसआई प्राचीन लिपि के हिन्दी और अंग्रेज़ी अनुवाद को लोगों के लिये डिस्प्ले करेगी।
- एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक जागेश्वर धाम के मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण कुछ शिलालेखों का अनुवाद डॉ. डीसी सरकार कर चुके हैं। डॉ. डी.सी. सरकार की इंडिका बुक में यह अनुवाद पूर्व में प्रकाशित हो चुका है, लेकिन मुख्य शिलालेखों का अनुवाद अब तक नहीं हो पाया है।
- विदित है कि एएसआई ने जागेश्वर और बद्रीनाथ के शिलालेखों के अनुवाद की मांग को लेकर करीब दो साल पहले भी एक पत्र एपिग्राफी शाखा को भेजा था। व्यस्तता के कारण विशेषज्ञों की टीम यहाँ नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन अब जल्द उसके यहाँ पहुँचने की उम्मीद जगी है।

मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना

चर्चा में क्यों?

22 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों को 'मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना' को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना' का उद्देश्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाज़ार उपलब्ध कराना है।
- इस हेतु प्रत्येक विकास खंड में महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों की किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शनी लगवाकर महिला समूहों को विपणन के लिये समुचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएंगे।
- महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को ब्लॉक स्तर पर बाज़ार मिलने से जहाँ उनको अपने उत्पादों की बिक्री के लिये एक मंच मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर उत्पादों को एक नई पहचान भी मिलेगी।
- प्रदेश में वर्तमान में 37 हज़ार से अधिक महिला समूह कार्यरत् हैं, जिनके द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। हालांकि, कई बार इनको सही बाज़ार न उपलब्ध होने के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
- इस योजना का संचालन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, जल्द होगा लागू

चर्चा में क्यों?

22 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिये गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार को मिलने के बाद इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा में स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड, देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन जाएगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता में समुदाय विशेष को कोई नुकसान नहीं होगा।
- विदित है कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित ड्राफ्ट कमेटी प्रदेश में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के प्रमुख हितधारकों से वार्ता कर ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। समिति ने डेढ़ साल में दो लाख से भी ज़्यादा लोगों के सुझाव, विचार लिये हैं।

स्मार्ट स्नेक-ट्रैपिंग डिवाइस

चर्चा में क्यों?

22 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ (यूपीईएस) के शोध छात्रों ने सांप पकड़ने वाला ऐसा उपकरण तैयार किया है, जो पलक झपकते ही बिना किसी को नुकसान पहुँचाए सांप को पकड़ लेगा।

प्रमुख बिंदु

- स्मार्ट स्नेक-ट्रैपिंग डिवाइस नामक इस परियोजना को केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी मंज़ूरी दी है। अब यूनिवर्सिटी की ओर से भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान में डिवाइस के परीक्षण के लिये अनुमति मांगी गई है।
- स्मार्ट स्नेक-ट्रैपिंग डिवाइस पर प्रधान अन्वेषक डॉ. नीलू ज्योति आहूजा के नेतृत्व में शोध छात्र हुमा नाज और राहुल चमोला तथा नितिन पासी की टीम काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह डिवाइस तैयार की जा रही है।
- डॉ. नीलू ज्योति आहूजा ने बताया कि इस डिवाइस का विकास सर्पदंश से मौत के मामलों को कम करने और विषरोधी दवाओं के विकास में किया जा सकेगा।
- इस डिवाइस सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिये विशेषतौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक कृत्रिम शिकार, माइक्रोकंट्रोलर, जीएसएम मॉड्यूल के साथ कैमरा और इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम लगाया गया है, जो बहुत सुरक्षित तरीके से सांपों को पकड़ सकता है, जबकि अभी तक सांपों को पकड़ने के लिये पारंपरिक तरीकों के साथ स्नेक स्टिक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।
- उन्होंने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में डिवाइस के परीक्षण के लिये उत्तराखंड वन विभाग से अनुमति मांगी गई है, ताकि डिवाइस का परीक्षण पूरा किया जा सके।
- इस संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि संस्थान की ओर से प्राप्त पत्र अनुमति के लिये शासन को भेज दिया गया है।
- गौरतलब है कि भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) के तहत किसी भी वन्यप्राणी पर शोध अनुसंधान इत्यादि के लिये राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। इसी क्रम में यूनिवर्सिटी की ओर से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के माध्यम से शासन को पत्र भेजा गया है।

नोट :

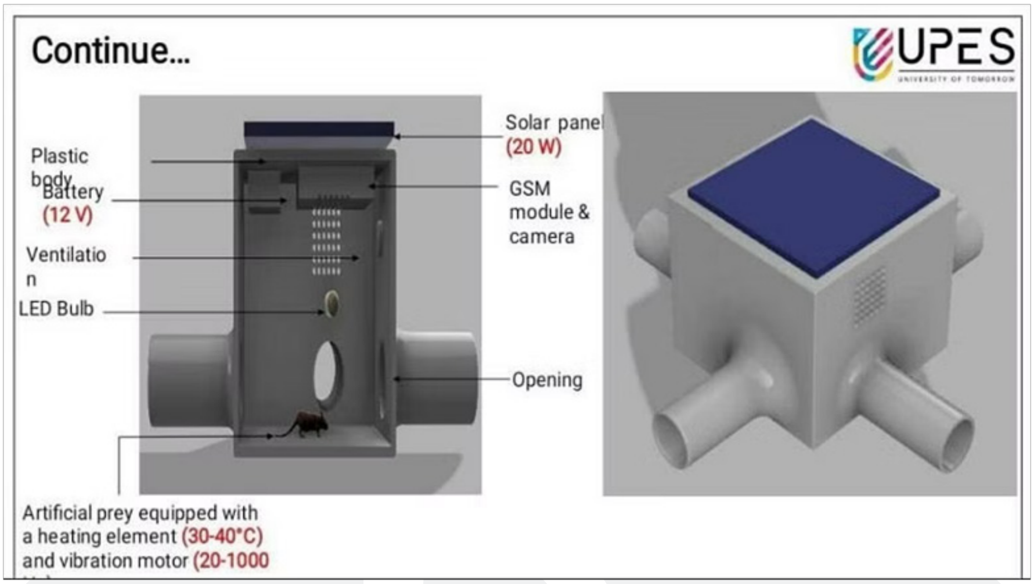

पीआरडी जवानों की ड्यूटी के दौरान मौत पर आश्रितों को मिलेंगे दो लाख रुपए

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लिये लागू कल्याणकोष नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जिससे सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान जवान की मौत पर मिलने वाली एक लाख की धनराशि को बढ़ाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं जवानों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि भी बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि प्रांतीय रक्षक एवं विकास दल के स्वयंसेवकों को दी जाने वाली सहायता को अधिक उपयोगी बनाने के लिये मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिये कल्याणकोष नियमावली में संशोधन के लिये वित्त एवं न्याय विभाग की सहमति ले ली गई है।
- इन प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी:
  - विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को 75 हज़ार की जगह डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे।
  - सामान्य डयूटी व यात्रा के दौरान मृत्यु पर 50 हज़ार रुपए की जगह एक लाख रुपए मिलेंगे।
  - स्थायी अपंगता पर उच्च श्रेणी के लिये अनुमन्य धनराशि की आधी एवं गंभीर घायल पर अनुमन्य की चौथाई धनराशि दी जाएगी।
  - उपचार के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को अधिकतम एक लाख रुपए मिलेंगे।
  - मृत्यु पर दाह संस्कार के लिये दस हज़ार रुपए मिलेंगे।
  - 3650 दिन की सेवा करने वाले जवानों को किसी वजह से सेवा से हटने पर एक लाख रुपए मिलेंगे।
  - सभी जवानों का बीमा किया जाएगा।
  - पीआरडी जवान को डयूटी एवं प्रशिक्षण के दौरान आपदा से नुकसान पर 50 हज़ार मिलेंगे।
  - अवैतनिक सदस्यों के आश्रित छात्रों को हाईस्कूल प्रथम श्रेणी पास करने पर श्रेष्ठ 10 बच्चों को 250 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी।
  - 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी पास 10 बच्चों को एक हज़ार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  - एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कॉलेज में एवं अन्य कोर्स में प्रवेश पर दो हज़ार रुपए हर महीने कोर्स की अवधि तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

नोट :

राष्ट्रीय फलक पर छाई उत्तराखंड की बेटी सृष्टि, फिल्म 'एक था गाँव' को मिला अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के कीर्तिनगर ब्लॉक के सेमला गांव निवासी सृष्टि लखेरा की फिल्म 'एक था गाँव' को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला है।

प्रमुख बिंदु

- सृष्टि लखेरा करीब 13 साल से फिल्म लाइन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उन्होंने 'एक था गाँव' फिल्म का प्रोडक्शन और निर्देशन किया है।

- फिल्म 'एक था गाँव' इससे पहले मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज (मामी) फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है।
- गढ़वाली और हिन्दी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज (पलायन से खाली हो चुके गाँव) की कहानी है।
- सृष्टि ने बताया कि उत्तराखंड में पलायन की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने यह फिल्म बनाई। पहले उनके गाँव में 40 परिवार रहते थे और अब पाँच से सात लोग ही बचे हैं। लोगों को किसी न किसी मज़बूरी से गाँव छोड़ना पड़ा। इसी उलझन को उन्होंने एक घंटे की फिल्म के रूप में पेश किया है

चमोली ज़िले को मिला राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

26 अगस्त, 2023 को 94 स्कॉच समिट कॉन्स्टीट्यूशन क्लब इंडिया नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप इंडिया की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली ज़िले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिये स्कॉच अवॉर्ड प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली ज़िले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिये स्कॉच अवॉर्ड में सिल्वर श्रेणी मिली है।
- चमोली के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. महेश कोहली (तत्कालीन ज़िला विकास अधिकारी चमोली) और संजय पुरोहित (ग्रामीण वित्त समन्वयक उपासक चमोली ग्रामीण विकास) ने यह अवॉर्ड प्राप्त किया।
- चमोली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की ओर से सदस्यों को लेंटाना फर्नीचर निर्माण, फल संरक्षण, पिरुल से बने उपयोगी सामान, धूप-अगरबत्ती निर्माण, कताई-बुनाई प्रशिक्षण, डेयरी प्रशिक्षण, सुगंधित जड़ी-बूटी प्रशिक्षण, भोजपत्र आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों को बैंक लिंकेज के साथ व्यवसाय के लिये ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
- चमोली में इस प्रकार के प्रशिक्षण से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोज़गार मिला है। इससे महिलाएँ स्वरोज़गार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। समूह की ओर से उत्पादित इन सामग्रियों से स्थानीय स्तर पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

उत्तराखंड में इसी साल से एमबीबीएस छात्रों को मिलेगा हिन्दी में पढ़ने का विकल्प

चर्चा में क्यों?

28 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा (एचएनबी) चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) हेम चंद्र ने दीक्षांत समारोह के दौरान मीडिया को बताया कि इस साल से एमबीबीएस दाखिले लेने वाले छात्रों को हिन्दी में पढ़ने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिये एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में पहली बार इसी सत्र से हिन्दी में एमबीबीएस की पढ़ाई का विकल्प छात्रों को देने के लिये एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हेमचंद्र के संरक्षण में एक समिति का गठन किया गया है।

- विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि छात्रों को आम बोलचाल की भाषा हिन्दी के साथ हिन्दी में पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा, जैसे- यकृत को लीवर ही लिखा गया है।
- इस कोर्स को हिन्दी में पढ़ाने के लिये शिक्षकों को भी अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अब हिन्दी व अंग्रेज़ी माध्यम के छात्र साथ बैठकर ही क्लास करेंगे।
- विदित है कि कभी हरिद्वार रोड पर दो कक्षों में चलने वाला एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय आज सेलाकुई के ईस्ट होपटाउन में 92 बीघा ज़मीन पर संचालित हो रहा है।

उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल छात्रों के लिये कीं कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

28 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा (एचएनबी) चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की कि राज्य के गरीब मेधावियों को अब एमबीबीएस, एमडी, एमएस की पढ़ाई करने के लिये राज्य सरकार आधी फीस देगी।

प्रमुख बिंदु

- विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कई अन्य घोषणाएँ भी की हैं-
  - मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये राज्य सरकार जल्द ही बीमा योजना लॉन्च करेगी। शोध को बढ़ावा देने के लिये उच्च शिक्षा की भाँति प्रोत्साहन योजना लागू होगी।
  - हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू होगा। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज वर्ष 2026 में और पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज 2027 में शुरू करेंगे।
  - राज्य के 5000 नर्सिंग पास छात्रों के लिये तीन देशों में रोज़गार के लिये सरकार ने एमओयू साइन किया है।
  - तीन हज़ार पदों पर नर्सिंग की भर्ती जल्द पूरी होने जा रही है। अब सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर भी बना रही है।
  - हिन्दी में एमबीबीएस की शुरुआत करने जा रहे उत्तराखंड में अब एमबीबीएस कोर्स में 16 संस्कार (गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार) को भी में शामिल किया जाएगा। इसके लिये जल्द ही समिति गठित की जाएगी।

उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तराखंड सरकार जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है। सबसे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय चयन समिति बनेगी, जो लोकायुक्त की तलाश के लिये खोजबीन (सर्च) कमेटी का गठन करेगी।

प्रमुख बिंदु

- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के एक उच्चाधिकारी ने लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान होने की पुष्टि की है।
- गौरतलब है कि नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिये हैं। इस कारण लोकायुक्ता की नियुक्ति का मामला खासा गर्म है।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकायुक्त व सदस्यों के चयन के लिये एक समिति बनाई जा रही है। समिति में विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नाम देने पर हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा दिये गए किसी विख्यात विधिवेत्ता को सदस्य बनाया जाना है।
- कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक, चयन समिति के चार नाम तय हो चुके हैं और पाँचवां नाम जल्द उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। गठन के बाद चयन समिति व्यक्तियों के नामों के पैनल तैयार करने के लिये एक सर्च कमेटी बनाएगी। सर्च कमेटी तीन गुना नामों की सिफारिश कर चयन समिति को भेजेगी। माना जा रहा कि धामी सरकार अगले दो-तीन महीनों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 'मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना' का शुभारंभ किया तथा कुछ खिलाड़ियों को दो-दो हज़ार रुपए का चेक भी प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना से उत्तराखंड के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे।
- इस योजना से राज्य के प्रत्येक जनपद से बालक एवं बालिका वर्ग में 100-100 खिलाड़ी लाभान्वित होगें।
- प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिमाह 02-02 हज़ार रुपए की छात्रवृत्ति एवं खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10-10 हज़ार रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना' के तहत खिलाड़ियों को चेक भी प्रदान किये।
- इस दौरान मुख्यमंत्री ने पैरालंपिक खिलाड़ियों एवं नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्तकर्त्ता अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को भी सम्मानित किया।
- राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में खेल से जुड़ी चार घोषणाएँ कीं-
- मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के खिलाडियों हेतु 200 बेड के छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
- हरि सिंह थापा स्पोट्र्स कॉलेज लेलू, पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों हेतु 50 बेड के छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
- उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भाँति 480 रुपए प्रतिदिन, प्रति खिलाड़ी किया जाएगा।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को साधारण बस एवं स्लीपर रेल किराया से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा थ्री टीयर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।

चंपावत में बनेगा राज्य का तीसरा साइंस सेंटर

चर्चा में क्यों?

30 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी देहरादून और अल्मोड़ा ज़िले के बाद अब जल्द ही चंपावत ज़िला मुख्यालय में राज्य के तीसरे साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- साइंस सेंटर के निर्माण संबंधी मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद राजस्व विभाग की ओर से चंपावत में साइंस सेंटर के निर्माण के लिये गौड़ी मार्ग पर 98 नाली ज़मीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है।
- लोक निर्माण विभाग की ओर से साइंस सेंटर के निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिये राज्य योजना में 35 लाख रुपए आवंटित किये गए हैं। डीपीआर बनाने के लिये दिल्ली की माथुर एंड कापरे एजेंसी को चयनित किया गया है।
- ज़िले में साइंस सेंटर का निर्माण होने से चंपावत के साथ ही ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ ज़िले के छात्र-छात्राओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं को लाभ मिलेगा।
- मुख्यालय में प्रस्तावित साइंस सेंटर में खगोल विज्ञान की जानकारी के लिये तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ऑडिटोरियम, इनोवेशन हट, ओवन पार्क का निर्माण भी होगा। साइंस सेंटर में कई वैज्ञानिक गतिविधियाँ होंगी। सेंटर में साइंस पार्क के साथ ही फन साइंस और थीम बेस्ड गैलरी भी बनाई जाएगी।

दृष्टि The Vision

नोट :